



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1497]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 20, 2006/अग्रहायण 29, 1928

No. 1497]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 20, 2006/AGRAHAYANA 29, 1928

गृह वंशालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2006

का.आ. 2119(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए क्या असम के यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असोम (उल्फा) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं अथवा नहीं, एतद्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल की अध्यक्षता में एक “विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण” का गठन करती है।

[फ. सं. 11011/47/2006-एन. ई-III]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2006

S.O. 2119(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes “The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal” consisting of Shri Justice Sanjay Kishan Kaul, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the United Liberation Front of Assam (ULFA) of Assam as Unlawful Association.

[F. No. 11011/47/2006-NE-III]

NAVEEN VERMA, Lt. Secy.